

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

# हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 20 अप्रैल, 2017 / 30 चैत्र, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग (स्टाम्प–रजिस्ट्रीकरण)

आदेश

शिमला-02, 17 अप्रैल, 2017

संख्याः रैव.1—3(स्टाम्प)6/80—III.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश और पंजाब नेशनल

बैंक, सर्किल ऑफिस शिमला के मध्य निष्पादित पट्टा विलेख की लिखित, जिसके द्वारा 10 बीधा भूमि को उद्यान विभाग द्वारा उक्त बैंक के पक्ष में सुन्नी, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश) में किसान प्रशिक्षण केन्द्र (एफ. टी.सी.) की स्थापना करने के लिए 99 वर्ष के लिए ₹ 1/− प्रतिवर्ष के पट्टा भाटक पर, पट्टे पर दिया गया था, पर प्रभार्य केवल ₹ 9,95,430/− (नौ लाख पचानवे हजार चार सौ तीस), की स्टाम्प शुल्क की रकम को इस आदेश के राजपत्र (ई−गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से छूट प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा, (तरूण श्रीधर), अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)।

\_\_\_\_\_

[Authoritative English Text of the Notification No. Rev.1- 3(Stamp)6/80-III dated 17-04-2017 as required under Article 348(3) of the constitution of India.]

# REVENUE DEPARTMENT (Stamp-Registration)

#### **ORDER**

Shimla-171002, the 17<sup>th</sup> April, 2017

No. Rev. 1-3(Stamp)6/80-III.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of subsection (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. II of 1899) as applicable to the State of Himachal Pradesh, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to remit the stamp duty amounting to ₹ 9,95,430/-(Nine Lacs Ninety Five Thousand Four Hundred and thirty only) chargeable on the instrument of lease deed executed between Horticulture Department and Punjab National Bank, Circle Office Shimla vide which 10 bighas of land was leased out by Horticulture Department in favour of the said Bank on lease rent of ₹ 1 per annum for the 99 years for establishment of the Farmers Training Centre (FTC) at Sunni, District Shimla (H.P), with effect from the publication of this order in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order, (TARUN SHRIDHAR), Addl. Chief Secy. (Revenue).

राजस्व विभाग (स्टाम्प–रजिस्ट्रीकरण)

आदेश

शिमला-02, 17 अप्रैल, 2017

संख्याःरैव01—3(स्टाम्प)6/80—III.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लाग रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 78 और 79 द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देते हैं कि उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश और पंजाब नेशनल बैक, सर्किल ऑफिस शिमला के मध्य निष्पादित पट्टा विलेख की लिखित, जिसके द्वारा 10 बीधा भूमि को उद्यान विभाग द्वारा उक्त बैंक के पक्ष में सुन्नी, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश) में किसान प्रशिक्षण केन्द्र (एफ.टी.सी.) को स्थापित करने के लिए 99 वर्ष के लिए ₹ 1/− प्रतिवर्ष के पट्टा भाटक पर, पट्टे पर दिया गया था, पर इस आदेश के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से ₹ 10/− (दस रूपए) की फीस प्रभारित की जाएगी।

आदेश द्वारा, (तरूण श्रीधर), अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)।

\_\_\_\_\_

[Authoritative English Text of the Notification No. Rev. 1-3 (Stamp)6/80-III dated 17-04-2017 as required under Article 348(3) of the constitution of India.]

# REVENUE DEPARTMENT (Stamp-Registration)

#### ORDER

Shimla-171002, the 17th April, 2017

No. Rev. 1-3(Stamp)6/80-III.—In exercise of the powers conferred upon him by sections 78 and 79 of the Registration Act, 1908 (XVI of 1908), as applicable to the State of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that a fee of ₹10/-(Rupees ten) shall be charged on the instrument of lease deed executed between the Horticulture Department and the Punjab National Bank, Circle Office Shimla *vide* which 10 bighas of land was leased out by the Horticulture Department in favour of the above said Bank on lease rent of ₹ 1 per annum for the 99 years for establishment of the Farmers Training Centre (FTC) at Sunni, District Shimla (H.P) with effect from the date of publication of this order in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order, (TARUN SHRIDHAR), Addl. Chief Secy. (Revenue).

तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 27 मार्च, 2017

संख्याः ईडीएन (टीई) ए(3)8/2015.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में प्रयोगशाला सहायक वर्ग—III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध— 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.——(1) (इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, प्रयोगशाला सहायक, वर्ग—III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2017 है।
  - (2) ये नियम राजपत्र, / ई-गजट, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, संजय गुप्ता, प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा)।

\_\_\_\_\_

उपाबन्ध-"क"

## हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में प्रयोगशालासहायक, वर्ग—III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नित नियम।

- **1. पद का नाम.**—प्रयोगशाला सहायक
- **2. पद (पदों) की संख्या.**—04 (चार)
- 3. वर्गीकरणं.—वर्ग—III (अराजपत्रित)
- **4 वेतनमान.**——(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमानः—— पे बैण्ड ₹ 5910—20200 / —जमा ₹ 1900 / —ग्रेड पे।
- (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियाँ : स्तम्भ संख्या 15—क में दिए ब्यौरे के अनुसार ₹ 7810 /— प्रतिमास ।
  - 5 **चयन पद अथवा अचयन पद.**—लागू नहीं
  - **6 सीधी भर्ती के लिए आय:.—**18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत् अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछडा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर / निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत

निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।

टिप्पणीः सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें कि पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

- 7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.——(क) अनिवार्य अर्हता (ए):—— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या स्कूल शिक्षा बोर्ड से विज्ञान वर्ग (स्ट्रीम) में 10+2 या इसके समतुल्य हो।
- (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो या हिमाचल प्रदेश सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा सम्यक रुप से मान्यता प्राप्त हो या किसी संस्थान से फार्मेसी (औषधि विज्ञान) में कम—से—कम दो वर्ष का डिप्लोमा कोर्स।
- (ख) वांछनीय अर्हता(ए):——हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
- 8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियां) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.——आयु :——लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताः---लागू नहीं।

- 9. परिवीक्षा की अविधि, यदि कोई हो.—(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनिधक ऐसी और अविधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।
- (ख) संविदा के आधार, सेवानिवृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगीं।
- 10. भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्निति/सैकेण्डमेंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
- 11. प्रोन्नति / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण किया जायेगा.— लागू नहीं।
  - 12. यदि विभागीय प्रोन्नित समिति विद्यमान् हो तो उसकी संरचना.——लागू नहीं।
- 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.——जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
- 14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
- 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/ प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

**15.क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियाँ नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी:—

(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में प्रयोगशाला सहायक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी ।

- (ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र मे आना : निदेशक, (तकनीकी शिक्षा) हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।
  - (ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
- (II) संविदात्मक उपलिख्यॉ.—संविदा के आधार पर नियुक्त प्रयोगशाला सहायक को ₹ 7810 / की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम् जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलिख्यों में ₹ 234 / की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रुप में अनुज्ञात की जाएगी।
- (III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.——निदेशक तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा/होगी ।
- (IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या, यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम सम्बद्ध भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
- (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.——जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय—समय पर गठित की जाए ।
- (VI) करार.—अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध—"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
- (VII) निबन्धन और शर्ते.——(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 7810 / —की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम् जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 234 / की दर से (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम् जमा ग्रेड का तीन प्रतिशत) बढ़ौतरी का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाए, जैसे वरिष्ट / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।
- (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश व पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सिहत गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनिधक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल० टी० सी० इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का काई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनिधकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनिधकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अविध अपवर्जित नहीं की जाएगी परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी / आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- (ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
- (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
- (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।
- (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों, जैसे एफ0आर0,एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम, आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे।
- 16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय—समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछडे वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

# **17. विभागीय परीक्षा.**—लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शिक्त.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को, किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध-ख

प्रयोगशाला सहायक एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य(नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप।
यह करार श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री श्री नेवासी, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वित्तीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख को किया गया।
"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने प्रयोगशाला सहायक के रुप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमित दी है :-
1. यह कि प्रथम पक्षकार प्रयोगशाला सहायक के रूप में से प्रारम्भ होने और को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अविध के लिए द्वित्तीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः
परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण करने के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी । 2. प्रथम पक्षकार की समेकित संविदात्मक रकम अर्थात ₹
Z• সপণ স্থাপ্য প্রাণ্যা রাণ্ডাপ্যেপ্য প্রেণ অপার 🕻 সার্থার হাণা।

- 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
- 4. संविदा पर नियुक्त प्रयोगशाला सहायक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूती अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सिहत गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनिधक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि कि लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त प्रयोगशाला सहायक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और उसे आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में, जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को

सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपरिथिति की अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- 6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
- 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
- 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर, पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।
- 9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ—साथ इ०पी०एफ० / जी०पी०एफ० भी लागू नहीं होगा। इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :			
(नाम व पूरा पता )			
2			
(नाम व पूरा पता			
साक्षियों की उपस्थिति में:	(प्रथम पक्षकार	के	हस्ताक्षर)
(नाम व पूरा पता)			
1			

(नाम व पूरा पता )

2	
(नाम व पूरा पता)	(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN (TE) A (3) 8/2015 dated: 27-03-2017 as required under article 348 (3) of the Constitution of India.]

# TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT

#### **NOTIFICATION**

Shimla-171002, the 27<sup>th</sup> March, 2017

**No. EDN (TE) A (3) 8/2015.**—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of **Laboratory Assistant Class-III**, (Non-Gazetted) in the Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training, Himachal Pradesh as per Annexure-'A' attached to this notification, namely.—

- 1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Technical Education, Vocational & Industrial Training Department, Laboratory Assistant, Class III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2017.
- (2). These rules shall come into force from the date of publication in the Rajparta/e-Gazette, Himachal Pradesh.

By order
SANJAY GUPTA
Principal Secretary (T.E.)

ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF LABORATORY ASSISTANT (NON-GAZETTED) CLASS-III (GOVERNMENT B. PHARMACY), IN THE DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING, HIMACHAL PRADESH, SUNDERNAGAR.

- 1 Name of the Pos.— Laboratory Assistant
- 2 Number of post(s).— 04 (four)
- **3** Classification.—Class-III (Non-Gazetted)

- **4** Scale of Pay.—(i) Pay Scale for regular incumbents : ₹ 5910-20200+ ₹ 1900 Grade Pay
  - (ii) Emoluments for Contract employees: ₹ 7810/- as per details given in Column No. 15-A
  - 5. Whether "Selection" Post or "Non-selection" post.—Not applicable
  - **6. Age for direct recruitment.**—18 to 45 years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on ad-hoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on ad-hoc or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other backward classes/other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous **Bodies** at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous **Bodies** after initial constitution of Public the Corporations/Autonomous Bodies.

**NOTE.**—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

- 7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).—
  (a) ESSENTIAL QUALIFICATION(s):—(i) 10+2 in Science Stream or its equivalent from a recognized University/Board of School Education.
- (ii) Alteast two years Diploma Course in Pharmacy from a recognized University or an Institute duly recognized by the Himachal Pradesh Government/Central Government.
- (b) DESIRABLE QUALIFICATION(s): Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
- 8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promote(s).—Age: Not Applicable.

Educational Qualification: Not Applicable

**9. Period of Probation, if any.**—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

- (b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.
- 10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
- 11. In case of recruitment by promotion/secondment/ transfer, grades from which promotion/ secondment/transfer is to be made.—Not Applicable
- 12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—Not Applicable
- 13. Circumstances under which the HPPSC is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
- **14.** Essential requirement for a direct recruitment.—A Candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India
- 15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type) /written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be.
- 15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below.—
- (I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Laboratory Assistant in the Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/ extended.

- **(b) POST FALLS WITH IN THE PURVIEW OF HPSSC.**—The Director (Technical Education) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur.
- (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

- (III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director (Technical Education) will be appointing and disciplinary authority.
- (IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contact appointment will be made on the basis of interview/personality test or if considers necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type) /written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency/authority i.e. Himachal Pradesh Staff Selection commission, Hamirpur.
- **(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT.**—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur from time to time.
- **(VI) AGREEMENT.**—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these rules.
- (VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ 7810/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 234/- (3% of minimum of the pay band+ grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
- (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
- (c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting in one month's service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days' maternity leave, 10 days' medical leave and 5 days' special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/ She shall not be entitled for Medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate for illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
- (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/ her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.
- (h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees.
- **16. Reservation.**—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

#### 17. Departmental Examination.—Not Applicable

information notice shall not be necessary:

18. Power to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

Provided that for—further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ₹...../- per month.

- 3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of contract appointee is not found satisfactory.

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and special leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. That Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contact appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- 6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative ground.
- 7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer /practitioner.
- 8. That contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
- 9. That Employees Group Insurance Scheme, EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:	
1	
(Name and full address)	(Signature of the FIRST PARTY)

348

### HOME (VIGILANCE) DEPARTMENT

#### **NOTIFICATION**

Shimla-2, the 19<sup>th</sup> April, 2017

**No. Home (Vig.) B (1)-2/2005.**—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation/revival of four posts of the following categories in State Vigilance and Anti Corruption Bureau in the pay scale shown against each.—

I.	Forest Ranger:	Rs.10300-34800 +Rs.4800 GP
2.	(Department of Forests). Excise & Tax. Inspector: (Excise & Taxation Deptt.)	Rs.10300- 34800+ Rs.3600GP
3.	Mining Inspector: (Industries Deptt.).	Rs. 5910-20200+Rs.2800 GP
4.	Inspector:	Rs.10300-34800+Rs.3200GP.

This expenditure will be incurred under Major Head 2062-Vigilance 00-104-Vigilance Commission of State 01- State Vigilance and Anti Corruption Bureau, (SOON-Non Plan) Demand No. 7 for smooth functioning of the Vigilance Bureau, HP.

(Himachal Road Transport Corporation)

This issues with the prior concurrence of the Finance Department obtained vide their U.O. No. Fin (PR)-B (7)-57/2010-loose dated 28-3-2017.

By order, Sd/-Principal Secretary (Home/Vig.),

### गृह विभाग

### अधिसूचना

शिमला-2, 13 अप्रैल, 2017

संख्याःगृह—सी(ई)1—1/2013.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वाले के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम,2007 (2008 का अधिनियम संख्यक 2) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची—2 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात्.—

# अनुसूची—2 का संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची—2 में विद्ययमान परिविष्ट "प्रतिबन्धित—3. इन्दिरा गांधी अस्पताल के गेट से लोअर बाईफरकेशन इन्दिरा गांधी अस्पताल (लक्कड़ बाजार) तक" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्.——

"प्रतिबन्धित-3. संजौली चौक से लोअर बाईफरकेशन इन्दिरा गांधी अस्पताल (लक्कड बाजार);"।

आदेश द्वारा, प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव (गृह)।

\_\_\_\_\_

[Authoritative English text of this Department Notification No. Home-C(E)1-1/2013 dated 13-4-2017 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

#### HOME DEPARTMENT

#### **NOTIFICATION**

Shimla-2, the 13<sup>th</sup> April, 2017

**No. Home-C(E)1-1/2013.**—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007, (Act No 2 of 2008), the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to make the following amendment in SCHEDULE- II appended to the said Act, namely.—

#### Amendment of SCHEDULI-II.

In SCHEDULE-II appended to the said Act, for the existing entry "R-3. From Gate of Indira Gandhi Hospital to Lower bifurcation Indira Gandhi Hospital (Lakkar Bazar)," the following entry shall be substituted, namely.—

"R-3. From Sanjauli Chowk to lower bifurcation Indira Gandhi Hospital (Lakkar Bazar),".

By order, PRABODH SAXENA, Principal Secretary (Home).

### ब अदालत प्रेम सरिता, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

श्री रवि कुमार पुत्र स्व0 श्री जगदीश चन्द, निवासी गांव ग्वाला, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0 प्र0 हाल गांव व डा0 पूर्वनी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

#### बनाम

आम जनता ग्राम ग्वाला / पूर्वनी, हि० प्र०

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रिव कुमार ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र उप मण्डल दण्डाधिकारी कल्पा स्थित रिकांग पिऔ के माध्यम से पेश किया है कि उनकी पुत्री कु0 निवृति का जन्म दिनांक 11—05—2010 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत पूर्वनी में नहीं किया गया है को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत पूर्वनी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपित हो तो वह दिनांक 02–05–2017 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत पूर्वनी को उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया।

मोहर।

(प्रेम सरिता), कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि० प्र०।

ब अदालत प्रेम सरिता, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

श्रीमती जीपू देवी पत्नी श्री मदन चन्द, गांव व डा० बारंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि० प्र०

#### बनाम

आम जनता ग्राम बारंग, तहसील कल्पा, हि० प्र०

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती जीपू देवी ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उनके पुत्र दिलदार का जन्म दिनांक 25–01–1999 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बारंग में नहीं किया गया है को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत बारंग के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 02–05–2017 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत बारंग को उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया।

मोहर।

(प्रेम सरिता), कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि० प्र०।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला—5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है